राज्यों ने किया PM-श्री योजना का विरोध

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइज़िंग इंडिया (PM-SHRI) योजना में भाग लेने में अनिच्छुक होने के कारण **दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल** को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत निधि आवंटित करना समाप्त कर दिया है।

- इस योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिये केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित **मौजूदा स्कूलों को अधिक दक्ष बनाकर 14,500 से अधिक पीएम-श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) स्थापित किये जाने** का प्रावधान शामिल है।
    - योजना के तहत व्यय का 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा तथा राज्यों को **शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर कर अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
- **पाँच राज्यों- तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने MoU पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।**
    - तमिलनाडु और केरल ने MoU पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है जबकि **दिल्ली, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने हस्ताक्षर करने** से **इनकार कर दिया** है जिसके कारण केंद्र ने उनके SSA फंड पर रोक लगा दी है।
- समग्र शिक्षा **स्कूली शिक्षा के लिये** एक **एकीकृत योजना** है जिसका दायरा **प्री-स्कूल से कक्षा XII तक** है और इसका उद्देश्य **स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों** पर समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
    - इसमें **सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और टीचर एजुकेशन (TE)** जैसी तीन योजनाएँ शामिल हैं।
        - इस योजना का मुख्य लक्ष्य **दो T- टीचर और टेक्नोलॉजी** पर ध्यान केंद्रित कर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

और पढ़ें: पीएम श्री स्कूल

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/states-oppose-pm-shri